

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 376/2017

तारीख 06.11.2017

सतीष श्रीवास्तव पुत्र मुक्तिनाथ श्रीवास्तव निवासी जटवाडा खुर्द तह.स.मा।— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

— रेस्पोंड


निर्णय

दिनांक 13.09.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा मिसल संख्या 481/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जटवाडा खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.10 बीघा किस्म सिवायचक पर संवत् 2070 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंड की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम जटवाडा खुर्द को सिवायचक भूमि मानने में अहम भूल की है यह है कि भूमि नगर पालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में स्थित है व आबादी भूमि है जिस पर अदालत मातहत को दफा 91 राज.लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। यह है कि आबादी भूमि अपीलान्त के पिता के समय से करीब 40 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है जिसमें अपीलान्त मकान बनाकर रह रहा है कोई काश्त का कार्य नहीं कर रहा है। यह है कि अपीलान्त का भूमि मुन्तनाजा पर 40 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है जो कानूनन अपीलान्त के नाम रेगुलाईजेशन होनी चाहिये किन्तु तहसीलदार साहब ने रेगुलाईज करने के बजाय भूमि से बेदखली का आदेश गैर कानूनी किया है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2014 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



वकील पेटाकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलग्न है तथा तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को मौके से बेदखल कर शास्ति आरोपित की गयी है न की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट को स्वयं को नोटिस की तामील करायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। सरकार पेटाकार द्वारा की गयी बहस में बताया गया गया है कि अपीलान्ट को भूमि से बेदखल किया गया तथा दण्ड स्वरूप शास्ति अधिरोपित की गयी है। प्रकरण में अपीलान्ट को सजा के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा मौके से बेदखल कर शास्ति अधिरोपित की गयी है जिसका हर्जाना अपीलान्ट को पटवारी हल्का को रसीद कटवाकर चुकाना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट द्वारा हर्जाना चुकाने की बजाय उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। जो सारहीन होने के कारण निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तथा अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 06.02.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर